



जिजा मजिस्ट्रेट
टांक

in his opinion, be necessary.

(1) Where the possession of any secured assets is required to be taken by the secured creditor or if any of the secured assets is required to be sold are transferred by the secured creditor under the provisions of this act, the secured creditor may, for the purpose of taking possession of control of any such secured asset, request, in writing the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate within jurisdiction any such secured asset or other documents relating thereto may be situated of found- to take possession thereof, and the Chief Metropolitan Magistrate or, as the case may be, the District Magistrate shall, on such request being made to him-

(a) Take possession of such asset and documents relating thereto, and

(b) Forward such assets and documents to the secured creditor.

(2) For the purpose of securing compliance with the provisions of sub-section (1) the Chief Metropolitan Magistrate or the District Magistrate may take or cause to be taken such steps and use or cause to be used, such force, as may, in his opinion, be necessary.

14- Chief Metropolitan Magistrate or District Magistrate to assist secured creditor in taking possession of secured asset-

न्यायिक दृष्टान्त, माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान की रिट याचिका संख्या 6256/2016 एकवर्कमर व अन्य बनाम जिजा मजिस्ट्रेट उदयपुर व अन्य, में पारित निर्णय दिनांक 04.10.2016 के अर्जुमार श्री जी एम 13 की उप धारा 2 के तहत नॉटिस जारी किया जाने व तामिल के पर्याय धारा 14 के तहत आदेश पारित करने से पूर्व पुनः श्री जी को नॉटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है। The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act 2002 की धारा 14 में उक्त रहन की गई सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी को दिलाये जाने बाबदे स्पष्ट प्रावधान है, जो इस प्रकार है.

प्रावर्ती एवं प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी बैंक / कम्पनी के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत नॉटिस जारी करने के पर्याय श्री जी एम की मांग की गई राशि का अप्रार्थीगण द्वारा भुगतान नहीं किया गया।

इसके आगे का ब्याज व अन्य खर्च बकाया निकलते है। उक्त श्री जी को प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत दिनांक 18.02.2025 को रजिस्टर्ड डाक नॉटिस जारी किया जाने तथा समाचार पत्र में प्रकाशित करवाये जाने के बावजूद श्री जी द्वारा आदेश मय ब्याज चुकाने में रूक की गई है। श्री जी द्वारा बन्धक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा श्री प्रार्थी बैंक/कम्पनी को नहीं सम्भालाया है। प्रार्थी बैंक / कम्पनी द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खारे में देय राशि क पुनर्भुगतान हेतु रहन श्रेय सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक / कम्पनी को जरिये पुलिस इमदद सम्भालने के लिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।



Handwritten signature and official stamp of the Director of Technical Education, Haryana.

आदेश आज दिनांक 06.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

वहन किया जायेगा।

वहनकर्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक/कम्पनी द्वारा प्रति भिजवाई जावे। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिनांक 06.05.2026 को कर्मचारियों के रखने हेतु जिला पुलिस अधीक्षक, टोंक को पर्याप्त पुलिस जाफा मुहैया कराने हेतु निर्णय स्वयं आदेश न हो। रहन रखी सम्पत्ति को कब्जा में लेते वकत कर्मचारी बर्नादे स्थितिगत कर लिया जावे कि रहन रखी सम्पत्ति के संबंध में किसी सक्षम न्यायालय का पालना करते हुए कब्जा में लेकर प्रार्थी को सम्मलवाया जावे। आदेश की पालना से पूर्व यह एसेट्स एण्ड एनफोर्समेंट ऑफ सिविल प्रोपर्टी एक्ट 2002 की धारा 31 के प्रावधानों की रहन रखी गई सम्पत्ति को दी सिविल प्रोपर्टी एण्ड डीकन्सर्टेशन ऑफ फाईनेंसियल निर्णय प्रति तहसीलदार टूनी को भेजकर निर्देश दिए जाते हैं कि प्रार्थी के पक्ष में

उत्तरदायित्व प्राधिकृत अधिकारी बैंक/कम्पनी का होगा।

है, यदि नियमों के अनुसार किसी प्रक्रिया/प्रावधान की पालना नहीं की गई है तो समस्त 2. आदेश प्राधिकृत अधिकारी के बाध्य पत्र एवं पेशा दरतावेजाल के आधार पर दिये जा रहे हैं तो उस आक्षेप का निस्तारण इस कार्यालय से करावे।

1. रहन शुरू सम्पत्ति का कब्जा लेकर सम्मलवाते वकत यदि नियमानुगत आक्षेप प्राप्त होता है तो सम्मलवाने के आदेश निम्न शर्तों पर दिए जाते हैं :

पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा रहन शुरू सम्पत्ति को प्रार्थी आदेश नहीं है। प्राधिकृत अधिकारी के कथन पर विचार कर उनके द्वारा दिये गये बाध्य नियमों के अनुसार समस्त कार्यावाही पूर्ण कर ली है। किसी भी न्यायालय से कोई स्वयं प्रार्थी के प्रावधानों के बाध्य पत्र के साथ इस आधार पर पेशा किया कि